

## Mains Matrix

### Table of content

1. रिकॉर्ड मौतें, गिरफ्तारियाँ और आत्मसमर्पण – नक्सल (माओवादी) उग्रवाद में गिरावट के संकेत
2. भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग का नया आयाम

### रिकॉर्ड मौतें, गिरफ्तारियाँ और आत्मसमर्पण – नक्सल (माओवादी) उग्रवाद में गिरावट के संकेत

#### 1. संदर्भ और पृष्ठभूमि

- **केंद्रबिंदु:** भारत में माओवादी (वामपंथी उग्रवाद - LWE) गतिविधियों में गिरावट।
- **मुख्य प्रमाण:** भौगोलिक क्षेत्र में तेज़ी से कमी, आत्मसमर्पण, गिरफ्तारियाँ और मौतों के रिकॉर्ड आँकड़े।
- **डेटा स्रोत:** साउथ एशिया टेररिज़म पोर्टल (SATP)
- **महत्व:** यह गिरावट भारत की सबसे पुरानी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक के ऐतिहासिक अवसान को दर्शाती है।

#### 2. गिरावट के प्रमुख संकेतक

संकेतक	वर्ष 2025 का आँकड़ा	तुलनात्मक स्थिति
आत्मसमर्पण	1,849 उग्रवादी	2016 और 2022 के बाद तीसरा सबसे अधिक आँकड़ा
गिरफ्तारियाँ	836 माओवादी	पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक
मौतें (उग्रवादी मारे गए)	333	2003 के बाद दूसरा सबसे अधिक वर्ष

#### • औसत (2000-2010 के दशक में):

- प्रति वर्ष लगभग 663 माओवादी गिरफ्तार,
- लगभग 496 मारे गए।
- **हालिया प्रवृत्ति:** 2020 के बाद पुनः वृद्धि, जो सुरक्षा अभियानों की तीव्रता को दर्शाती है।

#### 3. समय के साथ प्रवृत्तियाँ

- चार्ट 1:** आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या (2000–2025)
  - ➡ 2016, 2022 और 2025 में सबसे अधिक (2025 में 1,849 आत्मसमर्पण)।
- चार्ट 2:** गिरफ्तार उग्रवादियों की संख्या (2000–2025)
  - ➡ उतार-चढ़ाव वाला पैटर्न, 2025 में 836 पर चरम पर।
- चार्ट 3:** मारे गए उग्रवादियों की संख्या (2000–2025)
  - ➡ 2025 में 333 मौतें – 2003 के बाद दूसरा सबसे अधिक स्तर।

#### 4. सिकुड़ता भौगोलिक क्षेत्र (“रेड कॉरिडोर”)

वर्ष	प्रभावित ज़िलों की संख्या	प्रमुख राज्य
2013	176 ज़िले	झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश
2018	90 ज़िले	झारखण्ड (18), छत्तीसगढ़ (17), बिहार (16), ओडिशा (12), महाराष्ट्र (8) आदि
2025	45 ज़िले	अब मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा और आंशिक रूप

वर्ष	प्रभावित ज़िलों की संख्या	प्रमुख राज्य
		से महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश तक सीमित

#### 5. क्षेत्रीय पैटर्न (मानचित्र विश्लेषण)

मानचित्र	वर्ष	विवरण
मानचित्र 1	2013	केंद्रीय व पूर्वी भारत में फैला विस्तृत “रेड कॉरिडोर” जहाँ LWE हिंसा दर्ज हुई।
मानचित्र 2	2018	गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी, हिंसा कुछ क्षेत्रों तक सीमित।
मानचित्र 3	2025	और अधिक संकुचन, अब हिंसा केवल छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओडिशा की सीमावर्ती पट्टियों तक सीमित।

#### 6. व्याख्यात्मक सारांश

- “सिकुड़ता रेड कॉरिडोर” माओवादी उग्रवाद के तेज़ पतन को दर्शाता है।
- राज्य के सुरक्षा अभियानों, गिरफ्तारियों, और आत्मसमर्पणों ने

संगठनात्मक ढाँचे को कमज़ोर किया है।

- हालांकि, कुछ वन क्षेत्रों और अंतर-राज्यीय सीमाओं में छिटपुट हिंसा अभी भी जारी है।
- यह प्रवृत्ति बताती है कि अब उग्रवाद व्यापक आंदोलन से स्थानीयकृत militancy में परिवर्तित हो चुका है।

## 7. व्यापक निहितार्थ

- सुरक्षा के लिए:** भारत की आंतरिक सुरक्षा स्थिति अब काफी स्थिर हो चुकी है।
- शासन के लिए:** अब ध्यान विकास और एकीकरण पर केंद्रित किया जा सकता है, विशेषकर आदिवासी और वन क्षेत्रों में।
- नीतिगत आवश्यकता:** आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास, और पूर्व LWE क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना।

## 8. मुख्य संदेश

भारत में माओवादी उग्रवाद दो दशकों में अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुँच चुका है — रिकॉर्ड आत्मसमर्पण, बढ़ी गिरफ्तारियाँ और घटता क्षेत्रीय विस्तार यह संकेत देते हैं कि

वामपंथी उग्रवाद (LWE) अब भारत के सुरक्षा परिदृश्य में ऐतिहासिक गिरावट के चरण में प्रवेश कर चुका है।

### How to use

**माओवादी उग्रवाद में गिरावट: बहुआयामी रणनीति की सफलता का संकेत**

भारत में माओवादी उग्रवाद में आई गिरावट यह दर्शाती है कि मजबूत सुरक्षा उपायों, विकासात्मक पहुँच, और सुशासन संबंधी पहलों को एकीकृत रूप से लागू करने से आंतरिक सुरक्षा की दीर्घकालिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

यह उन आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने का मॉडल प्रस्तुत करता है जो सामाजिक-आर्थिक वंचना से उत्पन्न होती हैं।

### मुख्य प्रासंगिकता:

**GS Paper III – आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन**

### 1. विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध

#### कैसे उपयोग करें:

यह इस विषय का मूल सिद्धांत है। प्रस्तुत डेटा यह दर्शाता है कि राज्य की रणनीति कारगर साबित हुई है।

#### मुख्य बिंदु:

**(1) सुरक्षा-प्रथम दृष्टिकोण:**

2025 में रिकॉर्ड आँकड़े –

► 1,849 आत्मसमर्पण,

► 836 गिरफ्तारियाँ,

► 333 माओवादी मारे गए।

यह सब बेहतर खुफिया तंत्र, विशेष बलों (जैसे ग्रेहांडस), और घने वन क्षेत्रों में सुदृढ़ सुरक्षा चौकियों की स्थापना का परिणाम है।

**(2) भौगोलिक क्षेत्र का सिकुड़ना:**

सबसे निर्णायक संकेतक।

2013 में जहाँ 176 ज़िले प्रभावित थे, वहीं 2025 में यह घटकर केवल 45 ज़िले रह गए हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि उग्रवादियों का क्षेत्रीय आधार कमज़ोर पड़ गया है — जो उनके अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक था।

**(3) “गाजर और डंडा” नीति (Carrot and Stick Policy):**

उच्च आत्मसमर्पण दर केवल भय का परिणाम नहीं है, बल्कि सुसंगठित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास योजनाओं का भी फल है।

इससे उग्रवादियों का मनोबल गिरा है और भर्ती की दर कम हुई है।

**2. बाहरी राज्य और गैर-राज्य कारकों की भूमिका****कैसे उपयोग करें:**

हालाँकि यह यहाँ प्रमुख कारक नहीं है, परंतु माओवादी आंदोलन के पतन से यह सिद्ध होता

है कि घरेलू नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से आंतरिक, स्वदेशी समस्याओं का समाधान संभव है।

इससे बाहरी तत्वों को इन आंदोलनों का दुरुपयोग करने की संभावना घटती है।

**3. संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका****कैसे उपयोग करें:**

राज्य की सफलता का एक हिस्सा तकनीक और सूचना युद्ध (information warfare) के प्रभावी उपयोग में निहित है।

**मुख्य बिंदु:**

- सुरक्षा बलों ने निगरानी और खुफिया गतिविधियों के लिए तकनीकी साधनों का कुशल उपयोग किया।
- सरकार ने विकास कार्यों, पुनर्वास योजनाओं, और आत्मसमर्पण नीतियों को उजागर करने वाले अभियानों से माओवादी प्रचार को निष्प्रभावी किया।

**द्वितीयक प्रासंगिकता:****GS Paper II (शासन) एवं GS Paper I (समाज)****1. GS Paper II – शासन एवं विकास संबंधी नीतियाँ**

### कैसे उपयोग करें:

सुरक्षा संबंधी सफलता के पीछे विकासात्मक पहलों की ठोस भूमिका रही है।

### मुख्य बिंदु:

- सरकार की "National Policy and Action Plan to Address LWE" के अंतर्गत सड़क, टेलीकॉम, विद्यालय एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया।  
इससे उन शासन-रिक्त स्थानों (governance vacuum) को भरा गया जिनका लाभ माओवादी उठाते थे।
- SPARSHA (Surrender-cum-Rehabilitation Scheme) जैसी नीतियों ने आत्मसमर्पण दर बढ़ाने में सीधा योगदान दिया।

### 2. GS Paper I – सामाजिक सशक्तिकरण

### कैसे उपयोग करें:

माओवादी आंदोलन की जड़ें आदिवासी समुदायों के हाशियाकरण और वंचना में हैं।

### मुख्य बिंदु:

- दीर्घकालिक समाधान के लिए वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 जैसे कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

- रोज़गार और आजीविका के अवसर बढ़ाने से सामाजिक असंतोष कम होता है।
- हालिया आँकड़े यह दर्शाते हैं कि ये प्रयास — भले धीरे — सुरक्षा उपायों के साथ मिलकर प्रभाव दिखाने लगे हैं।

### निष्कर्ष:

माओवादी उग्रवाद की गिरावट भारत की सुरक्षा, विकास और शासन के समन्वित दृष्टिकोण की सफलता का प्रमाण है। यह मॉडल भारत की अन्य आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों — जैसे उग्रवाद, अलगाववाद और जातीय संघर्ष — से निपटने के लिए भी दिशा प्रदान

### भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग का नया आयाम

#### 1. संदर्भ और महत्व

#### घटना:

कैनबरा और सिडनी में आयोजित प्रथम भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता।

#### प्रतिभागी:

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष।

#### महत्व:

- एक दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा।
- रणनीतिक संवाद से आगे बढ़कर संचालनात्मक (operational) सहयोग की दिशा में ठोस कदम।
- 2020 में स्थापित **Comprehensive Strategic Partnership (CSP)** के और गहन होने का संकेत।

## 2. प्रमुख परिणाम और समझौते

### A. रणनीतिक ढाँचे (Strategic Frameworks)

- संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप (Joint Maritime Security Collaboration Roadmap) – समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय निगरानी को आगे बढ़ाने के लिए।
- संयुक्त रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर नवीकृत घोषणा (Renewed Joint Declaration) – 2014 के ढाँचे को सशक्त किया गया।

### B. संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanisms)

- वार्षिक रक्षा मंत्रियों की वार्ता (Annual Defence Ministers' Dialogue) – एक औपचारिक और निरंतर मंच के रूप में स्थापित।

- संयुक्त स्टाफ वार्ता मंच (Joint Staff Talks Forum) – संयुक्त अभ्यास, अभियान, और पारस्परिकता (interoperability) को आगे बढ़ाने हेतु।

## C. संचालनात्मक और तकनीकी सहयोग (Operational & Technical Cooperation)

- पारस्परिक पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर व्यवस्था (Mutual Submarine Rescue Support and Cooperation)।
- वायु से वायु ईंधन भरने (Air-to-Air Refuelling) व्यवस्था के क्रियान्वयन में प्रगति।
- सूचना-साझाकरण और रक्षा उद्योग संवाद (Defence Industry Roundtables) में विस्तार।
- भारतीय शिपयार्ड्स द्वारा ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक बेड़े की मरम्मत और रखरखाव में सहयोग की पेशकश।

## 3. रक्षा संबंधों का विकास

चरण	सहयोग का स्वरूप	प्रमुख विशेषताएँ
चरण I: रणनीतिक अभिसरण (Strategic Convergence)	कूटनीतिक एवं रणनीतिक	समान इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण; क्वाड के माध्यम से समन्वय; चीन की आक्रामकता पर साझा चिंता।
चरण II: संचालनात्मक गहराई (Operational Deepening)	सैन्य एवं सुरक्षा	संयुक्त अभ्यास (AUSINDEX, Malabar), खुफिया और लॉजिस्टिक सहयोग में वृद्धि।
चरण III: औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक अभिसरण (Industrial & Logistical Convergence)	रक्षा उद्योग एवं तकनीक	जहाज निर्माण, रखरखाव और सुरक्षित आपूर्ति शृंखला में सहयोग।

#### 4. साझेदारी के प्रेरक तत्व (Drivers of the Partnership)

##### संरचनात्मक कारक (Structural Factors)

- इंडो-पैसिफिक में बदलता समुद्री शक्ति संतुलन।
- क्षेत्र में चीन का दबावपूर्ण (coercive) व्यवहार।

##### व्यावहारिक कारक (Pragmatic Factors)

- पारंपरिक सुरक्षा प्रदाताओं पर अनिश्चितता के बीच आत्मनिर्भर सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकता।
- द्विपक्षीय लॉजिस्टिक, पनडुब्बी बचाव, और औद्योगिक सहयोग के माध्यम से संचालनात्मक घर्षण को कम करना।

##### पूरक ताकतें (Complementary Strengths)

भारत	ऑस्ट्रेलिया
भारतीय महासागर में सामरिक स्थिति	उन्नत रक्षा तकनीक
रक्षा उत्पादन में तेजी (~₹1.5 लाख करोड, FY 2024-25)	उच्च स्तरीय R&D और सहयोगी विशेषज्ञता

भारत	ऑस्ट्रेलिया
‘मेक इन इंडिया’ व iDEX के तहत किफायती निर्माण	अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म - P-8A Poseidon, MQ-4C Triton, “Ghost Shark” UUV

## 5. रणनीतिक महत्व और संकेत

### भारत के लिए:

- दक्षिणी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक पहुँच का विस्तार।
- समुद्री डोमेन जागरूकता और औद्योगिक साझेदारी को सुदृढ़ करना।

### ऑस्ट्रेलिया के लिए:

- AUKUS और अमेरिका से परे सुरक्षा साझेदारियों में विविधता।
- हिंद महासागर क्षेत्र में एक सक्षम और समान विचारधारा वाले साझेदार की प्राप्ति।

### संस्थागतकरण (Institutionalisation):

वार्षिक तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि सहयोग राजनीतिक बदलावों से परे जारी रहे। यह साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक जु़़ाव, और जन-से-जन संबंधों पर आधारित है।

## 6. सहयोग की प्रकृति और भविष्य की दिशा

### प्रकृति:

यह सहयोग क्रमिक (incremental) और परिवर्तनीय (reversible) है — जो अंतर-संचालन (interoperability), लॉजिस्टिक्स, और संकट प्रबंधन पर केंद्रित है, न कि किसी बाध्यकारी रक्षा संधि पर।

### भविष्य के प्रमुख क्षेत्र:

- लॉजिस्टिक और जहाज मरम्मत व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन।
- गोपनीय सूचना-साझाकरण ढाँचे का विस्तार।
- संयुक्त रक्षा-औद्योगिक परियोजनाओं में प्रगति।
- क्वाड पहलों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का समन्वय।

### संभावित प्रभाव:

यदि निरंतरता से लागू किया गया, तो यह साझेदारी –

- संचालनात्मक रूप से नियमित (routinised),
- रणनीतिक रूप से प्रभावशाली, और
- इंडो-पैसिफिक समुद्री स्थिरता की एक स्थिरकारी शक्ति बन जाएगी।

## 7. निष्कर्ष

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी अब संवाद से आगे बढ़कर क्रियान्वयन (deployment) की दिशा में विकसित हो चुकी है— जो एक परिपक्व और विश्वसनीय सामरिक संबंध का प्रतीक है।

साझा मूल्य, आपसी विश्वास, और समान हितों पर आधारित यह साझेदारी एक नियम-आधारित, सुदृढ़ और बहुधुवीय (multipolar) इंडो-पैसिफिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

#### How to use

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी एक व्यवहारिक (pragmatic) और सामरिक (strategic) प्रतिक्रिया है जो बदलते वैशिक शक्ति संतुलन के अनुरूप है। यह भारत के “गुटनिरपेक्ष अलगाव” (Non-Aligned Isolation) से निकलकर “बहु-संरेखित एकीकरण” (Multi-Aligned Integration) की ओर बढ़ने को दर्शाती है— जहाँ भारत समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ मिलकर स्वावलंबी और लचीली सुरक्षा संरचनाएँ बना रहा है ताकि चीन की आक्रामकता (Chinese Assertiveness) को संतुलित कर सके और मुक्त एवं खुले इंडो-पैसिफिक (Free and Open Indo-Pacific) की सुनिश्चितता कर सके।

#### प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

1. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैशिक समूह / समझौते जो भारत को प्रभावित करते हैं

#### कैसे उपयोग करें:

यह मुख्य अनुप्रयोग है। यह साझेदारी एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय पहल है जिसका क्षेत्रीय प्रभाव बहुत व्यापक है।

#### मुख्य बिंदु:

- संवाद से क्रियान्वयन तक (From Dialogue to Deployment): साझेदारी अब केवल रणनीतिक वार्ता तक सीमित नहीं है; यह पनडुब्बी बचाव, वायु से वायु ईंधन भरने, और जहाज मरम्मत जैसे संचालनात्मक सहयोग तक विस्तारित हो चुकी है। यह दर्शाता है कि संबंध प्रतीकवाद (symbolism) से आगे बढ़कर व्यवहारिक सहयोग (practical cooperation) तक पहुँच चुका है।

- क्वाड को सुदृढ़ करना (Strengthening the Quad): यह द्विपक्षीय साझेदारी क्वाड समूह (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के लिए एक “फोर्स मल्टीप्लायर” है, जो मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक के

- दृष्टिकोण को वास्तविक सैन्य शक्ति प्रदान करती है।
- चीन के प्रति रणनीतिक प्रतिकार (Strategic Counter to China): यह साझेदारी दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों, हिंद महासागर में उसकी नौसैनिक उपस्थिति, और ऋण-जाल कूटनीति (Debt-Trap Diplomacy) का संतुलन प्रस्तुत करती है — यद्यपि इसे प्रत्यक्ष रूप से "चीन-विरोधी गठबंधन" नहीं कहा गया है।

## 2. भारत और उसका पड़ोस – संबंध (India and its Neighborhood Relations)

कैसे उपयोग करें:

ऑस्ट्रेलिया भारत के इंडो-पैसिफिक पड़ोस में एक प्रमुख साझेदार है, और यह साझेदारी भारत की रणनीतिक पहुँच को विस्तारित करती है।

मुख्य बिंदु:

- विस्तारित पड़ोस (Extended Neighborhood): यह सहयोग भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" (Act East Policy) और SAGAR (Security and Growth for All in the Region) दृष्टिकोण के केंद्र में है।

- समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness – MDA): संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप (Joint Maritime Security Collaboration Roadmap) भारत को पूर्वी हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी में मदद करता है — जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

## द्वितीयक प्रासंगिकता: GS Paper III (सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी)

- सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमा क्षेत्रों में उनका प्रबंधन (Security Challenges and Management)

कैसे उपयोग करें:

यद्यपि यह सीमा-सुरक्षा से संबंधित नहीं है, परंतु यह व्यापक समुद्री सुरक्षा प्रबंधन का हिस्सा है।

मुख्य बिंदु:

- सुरक्षा साझेदारियों का विविधीकरण (Diversifying Security Partnerships): किसी एक साझेदार (जैसे रूस) पर निर्भरता घटाना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया भारत को पश्चिमी

प्रौद्योगिकी और उन्नत सैन्य मंचों तक पहुँच प्रदान करता है।

- लॉजिस्टिक और पारस्परिकता (Interoperability): पनडुब्बी बचाव (Mutual Submarine Rescue) और जहाज मरम्मत समझौते भारतीय नौसेना की संचालनात्मक क्षमता और पहुँच (reach) को दक्षिणी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत तक बढ़ाते हैं।

## 2. भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दे

कैसे उपयोग करें:

यह साझेदारी केवल सामरिक नहीं, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु:

- ‘मेक इन इंडिया’ के साथ तालमेल (Synergy with Make in India): ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक बेड़े की मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्डों की पेशकश भारत के रक्षा-उद्योग विकास और वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में एक ठोस कदम है।

- पूरक अर्थव्यवस्थाएँ (Complementary Economies): भारत की किफायती विनिर्माण क्षमता और विशाल कार्यबल, ऑस्ट्रेलिया के उन्नत अनुसंधान और तकनीकी प्लेटफॉर्म (जैसे "Ghost Shark" UUV) के साथ मिलकर ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Atmanirbhar Bharat) की दिशा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

## 3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

कैसे उपयोग करें:

यह साझेदारी उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी सहयोग और सह-विकास (Co-Development) पर आधारित है।

मुख्य बिंदु:

- नवाचार और सह-विकास (Innovation & Co-Development): iDEX (Innovations for Defence Excellence) ढाँचे के अंतर्गत पनडुब्बी ड्रोन (Underwater Unmanned Vehicles – UUVs) और अन्य उन्नत रक्षा प्रणालियों पर भारत-ऑस्ट्रेलिया का सहयोग तकनीकी स्वदेशीकरण

(Indigenization) का उत्कृष्ट उदाहरण है।

संक्षिप्त निष्कर्ष:

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी, भारत की नए युग की बहु-संरेखित विदेश नीति का प्रतीक

है—  
जहाँ लोकतांत्रिक सहयोग, सामरिक स्वायत्ता, और तकनीकी साझेदारी मिलकर एक मुक्त, सुरक्षित और संतुलित इंडो-पैसिफिक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं।



[WWW.MENTORAIAS.CO.IN](http://WWW.MENTORAIAS.CO.IN)

MENTORA IAS  
“YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT”